**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1088**

**23 मार्च, 2012 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: संविधान के भाग-9 ख का पारण**

**1088 श्री मणि शंकर अय्यर:**

क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि क्‍या सहकारी समितियों से संबंधित संविधान के भाग-9 ख का पारण पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा यथा कल्‍पित ग्रामीण भारत के समग्र विकास को सुनिश्‍चित करने के उद्देश्‍य से पंचायतों के विकास और कल्‍याण कार्यों सहित सहकारी समितियों के आर्थिक क्रियाकलापों में समन्‍वयन करने के लिए लाभदायक होगा ?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (डॉं. चरण दास महन्‍त)**

संविधान (सत्‍तानवेंवां संशोधन) अधिनियम, 2011 के भाग IXख में अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍न प्रावधान है:-

1. स्‍वैच्‍छिक निर्माण, लोकतांत्रिक सदस्‍य-नियंत्रण, सदस्‍य-आर्थिक भागीदारी और स्‍वायत्‍त कार्यप्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर सहकारी सोसायटियों का निगमीकरण, विनियमन तथा बंद किया जाना ।
2. एक सहकारी सोसायटी के निदेशकों की अधिकतम संख्‍या विनिर्दिष्‍ट करना जो इक्‍कीस सदस्‍यों से अधिक न हो।
3. बोर्ड और उसके पदधारियों के चुने गए सदस्‍यों के संबंध में चुनाव की तारीख से पांच वर्षों के निर्धारित कार्यकाल तथा सहकारी सोसायटी के चुनाव कराने हेतु एक प्राधिकरण अथवा निकाय का प्रावधान किया जाना।
4. छह माह की अधिकतम समय सीमा का प्रावधान किया जाना जिसके दौरान सहकारी सोसायटी के निदेशक मंडल को अधिक्रमण अथवा स्‍थगन के अधीन रखा जा सकता है।
5. स्‍वतंत्र व्‍यावसायिक लेखा परीक्षा का प्रावधान किया जाना।
6. सहकारी सोसायटी के सदस्‍यों के लिए सूचना का अधिकार का प्रावधान किया जाना।
7. सहकारी सोसायटियों के कार्यकलापों और लेखों की आवधिक रिपोर्टें प्राप्‍त करने के लिए राज्‍य सरकारों को अधिकार दिया जाना।
8. प्रत्‍येक सहकारी सोसायटी के बोर्ड में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के लिए एक सीट तथा महिलाओं के लिए दो सीटों जिनमें ऐसी श्रेणियों से वैयक्‍तिक रूप में सदस्‍य रखे जाते हों, के आरक्षण का प्रावधान।
9. सहकारी सोसायटियों के संबंध में अपराधों और इस प्रकार के अपराधों के संबंध में दण्‍ड का प्रावधान करना।

यह प्रत्‍याशा है कि ये प्रावधान न केवल सहकारी सोसायटियों के स्‍वायत्‍त एवं लोकतांत्रिक कार्यकरण को, बल्‍कि सदस्‍यों एवं अन्‍य पणधारियों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही भी सुनिश्‍चित करेगा । इसलिए सहकारी सोसायटियों से संबंधित उक्‍त अधिनियम के भाग IXख को पारित किए जाने से सहकारी सोसायटियों के आर्थिक कार्यकलापों को प्रोत्‍साहन मिलेगा जिससे ग्रामीण भारत की प्रगति में मदद मिलेगी ।

**\*\*\*\*\*\*\***